उत्सर्जन कटौती पर भारत के रुख में बदलाव नहीं

नई दिल्ली. विकासशील देशों से भी उत्सर्जन कटौती संबंधी बाध्यकारी शर्तें स्वीकार करने की पर्यावरण एवं वनमंत्री जयराम रमेश की अपील से उलट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को साफ कहा कि फिलहाल इन देशों को उत्सर्जन कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर भारत के इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्थायी विकास पर 11वें दिल्ली सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं और जो उत्सर्जन कटौती करने में सबसे ज्यादा सक्षम भी हैं। कटौती का भार भी उन्हें ही उठाना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए विकासशील देश बहुत कम जिम्मेदार हैं।

मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

दुनिया भर में ग्रीनहाउस जैसों के सकल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा केवल 4 प्रतिशत है। अगर भारत यह उत्सर्जन पूरी तरह रोक भी ले तो जलवायु परिवर्तन की मौजूदा स्थिति में शायद ही कोई फर्क पड़े।